# An Economics Study of New Eduction Policy 2020

KIJECBM V10 (2023) 86-93

Kaav International Journal of Economics, Commerce & Business Management

(A Refereed Peer Review Journal)

## नई शिक्षा नीति 2020 का एक आर्थिक अध्ययन

[1]डॉ देवेन्द्रसिंह बागरी

[1]*सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, शासकीय तुलसी महाविद्यालय, अनूपपुर*

**Received: Jan 03, 2022 Revised: Jan 18, 2023 Accepted: Jan 20, 2023**

**Article Info**

!SSN: 2348-4969
*Volume -10, Year-(2023)*
*Issue-01*
*Article Id:-*
*KIJECBM/2023/V-10/ISS-1/spl.iss /A-19*

© 2023 Kaav Publications. All rights reserved

**Abstract**

नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर एक अध्यादेश आया है अर्थात् एक बिल आया है। इसका नाम नेशनल हायर एज्यूकेशन बिल। इसे केबिनेट की मंजूरी प्राप्त हुई है। यह शिक्षा नीति से जुडा हुआ बिल है। अब यह बिल ससंद में जाएगा, ससंद से पास होगा और फिर लागू हो जाएगा। 1986 में राजीव गांधी की सरकार थी और उस समय 1986 शिक्षा नीति से लेकर अब 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुई है। यानी 34 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति लागू हुई है।

## प्रस्तावना

नई शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावना :-

National Education Policy 2020: नई शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिल गयी हैं, जो 34 वर्षों के बाद शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख और ऐतिहासिक निर्णय है। कैबिनेट ने मानव संसाधन और विकास मंत्रालय )MHRD) का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय भी कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सीखने पर ध्यान केंद्रित करना और "भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति" बनाना है। नई शिक्षा नीति )NEP) 2020 का प्रारूप पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन )ISRO) के प्रमुख केकस् .तूरीरंगन के नेतृत्व में विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा तैयार किया गया था।

NEP 2020 भारत में 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। स्वतंत्रता के बाद यह भारत की केवल तीसरी शिक्षा नीति है। शिक्षा के लिए पहली नीति 1968 में प्रख्यापित की गई थी और दूसरी 1986 में लागू की गई थी।

NEP 2020 का लक्ष्य 2040 तक एक कुशल शिक्षा प्रणाली बनाना है, जिसमें सभी शिक्षार्थियों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक समान पहुंच हो। इसका उद्देश्य एक नई प्रणाली का निर्माण करना है जो भारत की परंपराओं और मूल्य प्रणालियों पर निर्माण करते हुए SDG4 सहित 21वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षात्मक लक्ष्यों के साथ संरेखित हो। यह राज्यों, केंद्र द्वारा शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च को जीडीपी के 6% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित करता है।

 *Copyright 2023 Kaav Publications* 

PRINCIPAL
Govt. Tulsi College Anuppur
Distt. Anuppur (M.P.)

2015 में पूर्व केबिनेट सचिव टी एस आर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्य कमेटी बनाई गई थी। पहली कमेटी 2015 में बनाई गई थी, इसका कार्य नई शिक्षा नीति को लेकर एक मसौदा बनाना था । परन्तु यह मसौदा सरकार के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

दूसरी कमेटी 2016 में बनाई गई। यह कमेटी एक अन्तरिक्ष वैज्ञानिक केरंगन कस्तूरी . ने बनाई। केकस्तूरी . रंगन द्वारा जो मसौदा बनाया गया उसे31 मई 2019 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया। यह मसौदा 29 जुलाई 2020 को लागू कर दिया गया।

**National Education Policy:-**

- NEP 2020 का उद्देश्य 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 50% करना है।
- सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) का उद्देश्य बहु-विषयक संस्थान बनना होगा, जिनमें से प्रत्येक में 3,000 या अधिक छात्र होंगे।

**शिक्षक शिक्षा**

- 2030 तक, शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता चार वर्षीय एकीकृत बीएड. डिग्री होगी।.
- डिजिटल डिवाइड को पाटने में मदद करने के लिए शिक्षकों को भारतीय स्थिति से संबंधित ऑनलाइन शैक्षिक तरीकों का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

**स्कूली शिक्षा**

- अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत किया जाना है।
- शिक्षकों, और वयस्क शिक्षा के लिए स्कूलों में नयी National Curriculum framework पेश की जाएगी।
- कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगा।
- सिर्फ रट्टा सीखने के बजाय मुख्य ध्यान बच्चे के कौशल और क्षमताओं पर होगा।
- पाठ्यक्रम की संरचना में बड़े बदलाव
- आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के बीच कोई बड़ा अलगाव नहीं है।
- बोर्ड परीक्षाएं ज्ञान के अनुप्रयोग पर आधारित होंगी
- 5 + 3 + 3 + 4 पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना का पालन किया जाना है।
- कक्षा 6 के बाद से पाठ्यक्रम और व्यावसायिक एकीकरण में कमी की गयी है।
- भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का निर्माण )HECI)।
- 2025 तक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा )3-6 वर्ष की आयु सीमाको सार्वभौमिक बनाना। (
- 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जीईआर के साथ प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण।
- कक्षा 6 से कोडिंग और व्यावसायिक अध्ययन के साथ एक नया स्कूल पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा।
- कक्षा 5 तक शिक्षा के माध्यम के रूप में बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग किया जाएगा।
- एक नया पाठ्यचर्या ढांचा पेश किया जाना है, जिसमें प्री शामिल हैं।स्कूल और आंगनवाड़ी वर्ष-
- 2025 तक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन कक्षा 3 के स्तर पर बुनियादी कौशल सुनिश्चित करेगा।
- एनईपी द्वारा अनुशंसित स्कूल परीक्षा में सुधारों में छात्रों के पूरे स्कूल के अनुभव की प्रगति पर नज़र रखना शामिल है।
- इसमें कक्षा 3, 5 और 8 में राज्य जनगणना परीक्षा शामिल है।
- एक अन्य महत्वपूर्ण सिफारिश 10वीं बोर्ड परीक्षा के पुनर्गठन की थी जो मुख्य रूप से केवल कौशल, मूल अवधारणाओं और उच्चक्रम की सोच क्षमताओं पर - ध्यान केंद्रित करेगी और उनका परीक्षण करेगी।

**उच्च शिक्षा**

- विषयों के ढील के साथ शिक्षा के प्रति एक समग्र और बहुआयामी दृष्टिकोण
- UG प्रोग्राम में एकाधिक बार प्रवेशनिकास। उदाहरण / के लिए, व्यावसायिक और व्यावसायिक क्षेत्रों सहित एक अनुशासन में 1 वर्ष पूरा करने के बाद एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, 2 साल के अध्ययन के बाद एक

 *Copyright 2022 Kaav Publications* 

PRINCIPAL
Govt. Tulsi College Anuppur
Distt. Anuppur (M.P.)

डिप्लोमा और 3 साल के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी।

- 4-वर्षीय बहुविषयक बैचलर प्रोग्राम वैकल्पिक होगा।-
- यदि छात्र 4-वर्षीय प्रोग्राम में एक बड़ा अनुसंधान परियोजना पूरी करता है, तो उसे 'रिसर्च' की डिग्री दी जाएगी।
- M.Phil को बंद किया जाएगा।
- एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो एक छात्र द्वारा अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहीत करेगा।
- Research/Teaching Intensive विश्वविद्यालयों की स्थापना
- भारत के परिसर में विदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना
- हर शैक्षणिक संस्थान में, छात्रों के टेंशन और इमोशन को संभालने के लिए परामर्श प्रणाली होगी।
- कई प्रवेश और निकास विकल्पों के साथ चार वर्षीय स्नातक डिग्री शुरू की जाएगी।
- एमफि.ल की डिग्री समाप्त कर दी जाएगी।
- चिकित्सा, कानूनी पाठ्यक्रमों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षा के लिए नया अम्ब्रेला नियामक।
- संस्थानों के बीच हस्तांतरण को आसान बनाने के लिए एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी।
- कॉलेज संबद्धता प्रणाली को 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा, ताकि प्रत्येक कॉलेज या तो एक स्वायत्त डिग्री देने वाली संस्था या किसी विश्वविद्यालय के एक घटक कॉलेज के रूप में विकसित हो सके।
- इसका उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2018 में 26.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करना है, जिसमें अतिरिक्त 3.5 करोड़ नई सीटें हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: पारंपरिक ज्ञान

- आदिवासी और स्वदेशी ज्ञान सहित भारतीय ज्ञान प्रणालियों को सटीक और वैज्ञानिक तरीके से पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।
- यह आकांक्षी जिलों जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जहां बड़ी संख्या में छात्र आर्थिक, सामाजिक या जाति बाधाओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें 'विशेष शैक्षिक क्षेत्र' के रूप में नामित किया जाएगा।

एनईपी के उद्देश्य (राष्ट्रीय शिक्षा नीति) : -

नई राष्ट्रीय एजुकेशन नीति )NEP)का मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर शैक्षिक रूप से महाशक्ति बनाना तथा भारत में शिक्षा का सार्वभौम करण कर शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च करना है।

NEW NATIONAL EDUCATION POLICY का उद्देश्य शैक्षिक क्षेत्र में भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाना है और भारत के लिए नई शैक्षिक नीतियां के माध्यम से संपूर्ण भारत में शिक्षा का उचित स्तर प्रदान करना है जिससे शैक्षिक क्षेत्र की गुणवत्ता उच्च हो सके। भारत में बच्चों को तकनीकी तथा रचनात्मकता के सायसाथ शिक्षा की गुणवत्ता - का महत्व से अवगत कराना नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है जिससेशिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। शिक्षा में गुणवक्ता लाने के लिए यह केंद्र सरकार के तहत नई शिक्षा नीति को शुरू किया गया है।

National Education Policy (NEP) 5+3+3+4 Structure की विशेषता

- नई शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत के तीसरी शिक्षा नीति है जिसमें बुनियादी तौर पर बदलाव किए गए हैं।
- नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षिक क्षेत्र को तकनीकी से भी जोड़ा जाएगा जिसमें सभी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा डिजिटल एक्यूमेंट दिए जाएंगे।
- मानव जीवन के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है।
- नई शिक्षा नीति में सभी प्रकार की शैक्षिक विषय वस्तु को प्रमुखता उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा में भी ट्रांसलेट किया जाएगा जिससे शैक्षिक क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा मिल सके ।

 Copyright 2022 Kaav Publications 

PRINCIPAL
Govt. Tulsi College Anuppur
Distt. Anuppur (M.P.)

- छठवीं कक्षा से बच्चों को व्यवसायिक परीक्षण इंटर्नशिप दे दी जाएगी।
- नई शिक्षा नीति के भीतर अब पढ़ाई में कई प्रकार के अन्य विकल्प बच्चों को दिए जाएंगे। अब दसवीं कक्षा में अन्य विकल्पों को भी रखा जाएगा जिसमें छात्र कोई स्ट्रीम ना चुनकर अपनी इच्छा अनुसार विषयों को चुन सकेगा।
- नई शिक्षा नीति के अंतर्गत छात्रों को छठवीं कक्षा से ही कोडिंग सिखाई जाएगी।
- शैक्षिक क्षेत्र में वर्चुअल लैब को भी बनाया जाएगा जिससे शैक्षिक क्षेत्रों की गुणवत्ता को उच्च किया जा सके।
- नई शिक्षा नीति के तहत वर्षों से चली आ रही 10 + 2 के शैक्षिक पैटर्न को बदलकर 5+3+3+4 के नए शैक्षिक पैटर्न को चुना गया है जिसमें 3 साल की फ्री New Education Policy PDF (NEP) नेशनल एजुकेशन पालिसी 2020 – नई शिक्षा नीति | National education policy स्कूली शिक्षा बच्चों को दी जाएगी।
- नई शिक्षा नीति के भीतर शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा जिसमें कुछ शैक्षिक क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है जैसे मेडिकल तथा ला।

*नई शिक्षा नीति 2020 के मुख्य तथ्य :-*

- नई शिक्षा नीति के माध्यम से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का गठन किया जाएगा जिसमें छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए क्रेडिट को डिजिटल अकैडमी क्रेडिट बनाया जाएगा और विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों के माध्यम से इन क्रेडिट को संग्रहित कर छात्र के अंतिम वर्ष की डिग्री में स्थानांतरित करके सभी क्रेडिट को एक साथ जोड़ा जाएगा।
- नेशनल एजुकेशन पालिसी 2020 के अंतर्गत शैक्षिक पाठ्यक्रम को लचीला बनाए जाने की हर संभव कोशिश की जा रही है । यदि कोई छात्र किसी शैक्षिक कोर्स में रुझान ना रखने के कारण उस शैक्षिक कोर्स के बीच में दूसरा कोर्स पढ़ना चाहता है तो वह अपने पहले कोर्स से निश्चित समय अवधि तक रुक कर दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है।
- नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक हर जिले में उच्च शिक्षा संस्थान का निर्माण किया जाना नई शिक्षा नीति के भीतर सम्मिलित है।
- नई शिक्षा नीति के भीतर 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बहु विषयक शैक्षिक पाठ्यक्रम संस्थान बनाने का उद्देश्य रखा गया है।
- नई शिक्षा नीति के भीतर स्नातक कोर्स को 3 से 4 साल तक बढ़ा जा सकता है जिसमें छात्रों को बहु विकल्प प्रदान किए जाएंगे। इन सभी बहु विकल्पों के उचित प्रमाण पत्र के अनुसार छात्रों को डिग्री दी जाएगी। उदाहरण यदि कोई छात्र 1 साल के लिए स्नातक कोर्स की पढ़ाई करता है तो उसे केवल एक साल की पढ़ाई का ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा और 2 साल बाद उसे एडवांस डिप्लोमा का प्रमाण पत्र दिया जाएगा और 3 साल बाद उचित प्रमाणों के आधार पर उसे डिग्री दी जाएगी अंत में 4 साल के बाद छात्र को बैचलर डिग्री के साथ साथ रिसर्च की डिग्री भी दी-जाएगी।
- राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा को आयोजित करेगी जिससे शिक्षा का स्तर बनाया जा सके।
- नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों को एक समान माना जाएगा।
- नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय उच्च शिक्षा आयोग को 4 वर्टिकल दिए गए हैं जिसमें नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल , हायर एजुकेशनल काउंसिल , जर्नल एजुकेशन काउंसिल तथा नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल को रखा गया है।
- ईलर्निंग पर जोर देना ताकि किताबों पर निर्भरता - म हो सके।क
- नई शिक्षा नीति के माध्यम से दिव्यांग जनों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है।

न्यू एजुकेशन पालिसी 2020 के लाभ :-

नेशनल एजुकेशन पालिसी 2020 के माध्यम से लाभार्थियों को कौनकौन से लाभ प्रदान किये जाएंगे। उन - नीचे दी जा रही है। सभी लाभों की सूची लेख में New

 Copyright 2022 Kaav Publications 

PRINCIPAL
Govt. Tulsi College Anuppur
Distt. Anuppur (M.P.)

Education Policy लाभों की पूरी जानकारी नीचे दी गयी सूची से प्राप्त कर सकते हैं।

- नई शिक्षा नीति के माध्यम से शैक्षिक क्षेत्र में तकनीकी को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- नई शिक्षा नीति के माध्यम से शैक्षिक पाठ्यक्रम में भाषाओं को लेकर कई विकल्प रखे गए हैं। यदि शैक्षिक पाठ्यक्रम में कोई छात्र अपनी क्षेत्रीय भाषा अथवा मातृभाषा को पढ़ना चाहता है तो वह आसानी से उन्हें पड़ सकता है। वही इस शैक्षिक पाठ्यक्रम में भारतीय प्राचीन भाषाओं को पढ़ने का भी विकल्प छात्रों के समक्ष रखा गया है।
- नई शिक्षा नीति में 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा तीन तक के सभी छात्रों के लिए संख्यात्मक ज्ञान तथा साक्षरता को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की योजना तैयार की जाएगी।
- स्वास्थ्य नीति के तहत छात्रों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाएगा जिसके साथ छात्रों के लिए स्वास्थ्य कार्ड भी बनाये जाएंगे।
- नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षकों को समय-समय पर उनके कार्य प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नति को भी रखा गया है।
- नई शिक्षा नीति में 2030 तक अध्यापन के लिए b.ed की डिग्री को 4 वर्ष की न्यूनतम डिग्री योग्यता में सम्मिलित कर दिया गया है । यानी 2030 तक b.ed का कोर्स 4 साल का हो चुका है।
- नई शिक्षा नीति के भीतर हायर एजुकेशन से संबंधित एमफिल की डिग्री को भी खत्म किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए व्यवसायिक मानक को विकसित करेगी तथा एनसीईआरटी के परामर्श पर अध्यापकों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक पाठ्यक्रम की चर्चा की विषय वस्तु को भी तैयार किया जाएगा।
- छात्रों को जिस क्षेत्र में अधिक रूचि है जैसे – खेल, कला, बॉक्सिंग, आदि में छात्रों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- नई शिक्षा नीति में शैक्षिक पाठ्यक्रम के साथसाथ - उनके कौशल पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा वही मेन सिलेबस में भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को शामिल किया जा रहा है।
- छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए हर संभव कोशिश नई शिक्षा नीति में की गई है । जिसमें पढ़ाई को आसान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल शैक्षिक पाठ्यक्रम में किया जाएगा।
- छात्रों पर बोर्ड परीक्षाओं का बोझ कम करने के लिए बोर्ड परीक्षाओं की रूपरेखा को भी बदला जाएगा जिसमें 1 साल में दो बार छात्रों की परीक्षाएं की जाएंगी।
- छात्रों को ऑफलाइन कक्षाओं के साथ ऑनलाइन माध्यम से भी पाठ्यक्रमकोर्स उपलब्ध करवाए / जाएंगे।
- महाविद्यालयों की स्वायत्ता 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी तथा क्रमिक सहायता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना भी की जाएगी।
- देश के बड़े संस्थान जैसे आईआईटी और आईआईएम के लिए वैश्विक स्तर पर मानकों हेतु बहु विषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना भी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कराई जाएगी।
- वहीं कानूनी तथा चिकित्सा क्षेत्र को छोड़कर उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक कल निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा।
- शैक्षिक पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने तथा उसे तकनीकी माध्यम से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी जिससेशिक्षा तथा प्रशासनिक क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से विचारों का आदान प्रदान संभव हो सके।

नेशनल एजुकेशन पालिसी 2020 के चरण :-

- फाउंडेशन स्टेज -: नई शिक्षा नीति के फाउंडेशन स्टेज में 3 से 8 साल तक के बच्चों को सम्मिलित किया गया है। जिसमें 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा को सम्मिलित किया गया है जिसके अंतर्गत छात्रों का भाषा कौशल तथा शैक्षिक स्तर का मूल्यांकन किया जाएगा और उसके विकास में ध्यान केंद्रित किया

 Copyright 2022 Kaav Publications 

PRINCIPAL
Govt. Tulsi College Anuppur
Distt. Anuppur (M.P.)

जाएगा।

प्रीपेटरी स्टेज -: इस स्टेज में 8 से 11 साल के बच्चों को सम्मिलित किया गया है जिसमें 3 से कक्षा 5 तक के बच्चे होंगे। नई शिक्षा नीति के इस स्टेज में छात्रों का संख्यात्मक कौशल को मजबूत करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा वहीं सभी बच्चों को क्षेत्रीय भाषा का भी ज्ञान दिया जाएगा। मिडिल स्टेज -: इस स्टेज के भीतर छठवीं से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को सम्मिलित किया गया है जिसमें छठवीं कक्षा के बच्चों से से ही कोडिंग सिखाना शुरू की जाएगा । वही सभी बच्चों को व्यवसायिक परीक्षण के साथसाथ व्यवसाय इंटर्नशिप - के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे । सेकेंडरी स्टेज :- इस स्टेज में आठवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को सम्मिलित किया गया है। इस स्टेज के भीतर आठवीं से 12वीं कक्षा के शैक्षिक पाठ्यक्रम को भी खत्म करके बहु वैकल्पिक शैक्षिक पाठ्यक्रम को शुरू किया गया है। छात्र किसी निर्धारित स्ट्रीम के भीतर नहीं बल्कि अपनी मनपसंद के अनुसार अपने विषयों को चुन सकते हैं। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत छात्रों को विषयों को चुनने को लेकर स्वतंत्रता दी गई है , छात्र साइंस के विषयों के साथ-साथ आर्ट्स या कॉमर्स के विषय को भी एक साथ पढ़ सकते हैं।

नेशनल एजुकेशन पालिसी पाठ्यक्रम में क्या बदलाव हुए हैं :-

- कक्षा तीसरी से पांचवीं तक के छात्रों को प्रतिदिन 2 घंटे का गृह कार्य दिया जाएगा।
- कक्षा 6 से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 1 घंटे का होम वर्क दिया जाएगा।
- कक्षा 9 से 12 वीं तक के छात्रों को 2 घंटे का होम वर्क दिया जाएगा।
- छात्रों का बैग उनके वजन से केवल 10% अधिक होना चाहिए।
- जो छात्र एलकेजी, यूकेजी में पढ़ते हैं उन्हें कोई होम वर्क नहीं दिया जाएगा।
- इसके अलावा पहली कक्षा व दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को भी गृह कार्य नहीं दिया जाएगा।
- जब छात्रों के लिए पुस्तकों का चयन किया जाएगा उसके साथ किताबों के वजन पर भी ध्यान दिया जाएगा।
- छात्रों के लिए स्कूलों में बाथरूम व पानी की सही सुविधा होनी चाहिए।

2025 तक पूर्वप्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण- :-

- आंगनवाड़ियों को मजबूत बनाना।
- नए प्रीस्कूल खोलना।-
- प्राथमिक शिक्षा के साथ लिंक।
- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का विस्तार।

2025 तक सभी के लिए मूलभूत साक्षरतासंख्यात्मकता/ :-

- भाषा गणित/– गुणवता शिक्षण सामग्री पर ध्यान।
- नेशनल ट्यूटर कार्यक्रम।
- स्कूल की तैयारी माॅड्यल।
- उपचारात्मक निर्देशात्मक सहायता कार्यक्रम।
- शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 से कम हो।

नई पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना :-

- 5 + 3 + 3 + 4 डिजाइन उम्र)3-18)।
- मूलभूत चरण प्राथमिक और ग्रेड-पूर्व)1-2)।
- प्रारंभिक चरण ग्रेड)3-5)।
- मध्य चरण ग्रेड)6-8)।
- माध्यमिक चरण ग्रेड)9-12)।
- केवल शैक्षिक पुनर्संरचना, स्कूलों की कोई भौतिक पुनर्संरचना नहीं।

पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र का परिवर्तन :-

- भाषा दक्षता, वैज्ञानिक स्वभाव, सौंदर्य बोध, नैतिक तर्कश्, डिजिटल साक्षरता, भारत का ज्ञान, सामयिकी का विकास करना।
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को सभी भाषाओं में संशोधित किया जाएगा।
- भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली नई पाठ्यपुस्तकें।
- लचीलापाठ्यक्रम और मूल्यांकन। एकीकृत/

 Copyright 2022 Kaav Publications 

PRINCIPAL
Govt. Tulsi College Anuppur
Distt. Anuppur (M.P.)

देश के हर बच्चे के लिए समान और समावेशी शिक्षा :-

- कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों )URGS) पर विशेष ध्यान
- लिंग (महिला और ट्रांसजेंडर),
- सामाजिक.सांस्कृतिक (अ.जा-,अ.ज.जा., अ.पि.व., मुस्लिम, प्रवासी समुदाय(,
- विशेष आवश्यकताएं सीखने और शारीरिक) (अक्षमता, और
- सामाजिक(आर्थिक स्थिति (शहरी गरीब-
- मुस्लिमों और अन्य शैक्षणिक रूप से अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहित करने के लिए हस्तक्षेप।

रणनीतियाँ :-

- वंचित क्षेत्रों में विशेष शिक्षा जोन।
- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कोष।
- लक्षित जिलों को वित्त पोषण और सहायता प्रदान करना।
- यूआरजी शिक्षक भर्ती।
- 25: 1 शिष्यशिक्षक अनुपात।-
- समावेशी स्कूल वातावरण और पाठ्यक्रम।
- मदरसों, गुरुकुल, पाठशालाओं, को अपनी परंपराओं को संरक्षित करने और NCF को सिखाने और एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया।
- शहरी गरीबों पर ध्यान देना।

यूनिवर्सल एक्सेस एड रिटेंशन :-

2030 तक सभी स्कूल शिक्षा के लिए 100% सकल नामांकन अनुपात

- मौजूदा स्कूलों में प्रवेश में वृद्धि।
- रेखांकित स्थानों में नई सुविधाएँ।
- परिवहन और छात्रावास सुविधाओं द्वारा समर्थित स्कूल युक्तिकरण।
- उपस्थिति, ड्रॉप आउट, स्कूल के बहार के बच्चों और सीखने के परिणामों पर नजर रखना।
- दीर्घकाल तक स्कूल न जाने वाले किशोरों के लिए कार्यक्रम।
- सीखने के लिए कई रास्ते - औपचारिक और गैर-औपचारिक मोड, ओपन स्कूलिंग, प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों को मजबूत करना।
- शिक्षा का अधिकार ग्रेड 12 तक बढ़ाया जाए।

भाषा :-

बच्चे 2-8 वर्षों के बीच सबसे जल्दी भाषा सीखते हैं, और बहुभाषावाद के छात्रों के लिए महान संज्ञानात्मक लाभ हैं-

- शिक्षा के माध्यम के रूप में घरेलू भाषामातृभाषा।/
- प्री स्कूल और ग्रेड-1 से छात्रों को तीन या अधिक भाषाओं के लिए एक्सपोजर।
- तीन भाषा सूत्र में लचीलापन: छात्र ग्रेड-6 या 7 में तीन भाषाओं में से एक या एक से अधिक बदल सकते हैं।
- केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बडी संख्या में क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की भर्ती करना।
- माध्यमिक विद्यालय के दौरान वैकल्पिक के रूप में विदेशी भाषा का चुनाव।
- संस्कृत को वैकल्पिक भाषाओं में एक के रूप में पेश किया जा सकता है।
- स्कूलों में तमिल, तेलुगू, कन्नड, मलयालम, ओडिया, पाली, फारसी, और प्राकृत सहित अन्य शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य का शिक्षण।

**निष्कर्ष :-**

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक अच्छी नीति है। क्योंकि इसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को समग्र, लचीला, बहु-विषयक बनाना है। जिसमे नीति का आशय कई मायनों में आदर्श प्रतीत होता है। लेकिन यह वह कार्यान्वयन है, जहां सफलता की कुंजी निहित है।

नई शिक्षा नीति कई उपक्रमों के साथ रखी गई है, जो वास्तव में वर्तमान परिदृश्य की जरूरत है। नीति का संबंध अध्ययन पाठ्यक्रम के साथ कौशल विकास पर ध्यान देना है। किसी भी चीज के सपने देखने से वह काम नहीं करेगा, क्योंकि उचित योजना और उसके अनुसार काम करने से केवल उद्देश्य पूरा करने में मदद मिलेगी। जितनी जल्दी

 Copyright 2022 Kaav Publications 

PRINCIPAL
Govt. Tulsi College Anuppur
Distt. Anuppur (M.P.)

**E-mail: hegtdcano@mp.gov.in** ☎9893076404

एनईपी के उद्देश्य प्राप्त होंगे, उतना ही जल्दी हमारा राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर करेगा।

स्कूल कॉलेज में अन्य विषयों के अतिरिक्त संस्कृत के पढ़ाई पर भी जोर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थानों में भी आर्ट्स और ह्यूमनिटीज के विषय पढ़ाए जाएंगे, जिससे विज्ञान के बालक भी अन्य क्षेत्रों में अपनी योग्यता से कुछ बेहतर कर पाएंगे। इस तरीके से नई शिक्षा नीति के कारण बच्चे व्यवहारिक ज्ञान लेकर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे।

## सन्दर्भ :-

1- www.google.com/wikipedia.com
2- www.wikipedia.com

PRINCIPAL
Govt. Tulsi College Anuppur
Distt. Anuppur (M.P.)